वोटिंग मशीनमें पाई गई थी तकनीकी गड़बड़ी

सुलतानपुर मामले में जिलाधीश की सफाई

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

बुलढाणा- बुलढाणा में फरवरी 2017 में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान लोणार तहसील के ग्राम सुलतानपुर स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 57/6 पर वोटिंग मशीन में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई थी. सुलतानपुर में एक ही वोटिंग मशीन में गड़बड़ी थी, जांच में अन्य मतदान केंद्रों की वोटिंग मशीनें सहीं पाई गई थीं. इस पुष्टि के बाद ही मतदान प्रक्रिया पर अमल किए जाने की सफाई बुलढाणा के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है.

इस मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान करा, 23 फरवरी 2017 को

परिणाम घोषित किया गया था. जिले में 60 जिला परिषद और 120 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ था. इस चुनाव के लिए 1691 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई थी.

3 हजार 382 वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया था. हर मतदान केंद्र पर जिला परिषद और पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वतंत्र वोटिंग मशीनें लगाई गई थीं. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन मशीनों में से सुलतानपुर के 57/6 नंबर के मतदान केंद्र पर लगी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी. इसी मतदान केंद्र पर पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगी वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी. जिले के शेष 1690 मतदान केंद्रों से इस तरह की कोई शिकायत जिला प्रशासन को नहीं मिली. सुलतानपुर के मामले को लेकर कोई याचिका भी दायर नहीं हुई है.

लीची का अधिक सेवन बच्चों के लिए हानिकारक

बना सकता है मिर्गी का मरीज

छोटे बच्चों को लीची न दें

डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि छोटे बच्चों को लीची न दें. खासकर रात के समय तो बिलकुल भी नहीं. जनजागृति करने पर ऐसी मौत की घटनाओं में सालाना 400 से घटाकर 50 पर लाने में सफलता मिली है.

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

नागपुर- मीठी रसीली लीची का स्वाद सभी को भाता है, पर खाली पेट इसका ज्यादा सेवन करने से खून में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, इससे शरीर में घातक रसायन तैयार होते हैं जिससे मिर्गी का अटैक आता है. इससे मरीज के बेहोश होने या मौत की आशंका ज्यादा हो जाती है. बिहार के मुजफ्फरपुर में 2014 में 122 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. देश में मुजफ्फरपुर की लीची काफी प्रसिद्ध है.6 साल पहले मुजफ्फरपुर में प्रवीण को रात के समय मिर्गी का अटैक आया. वह बेहोश हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया,पर उसकी मौत हो गई. ऐसी स्थिति मुजफ्फरपुर में रहने वाले कई बच्चों की हुई. 1995 में बिहार में इस बीमारी से कई बच्चों की मौत हुई. इस बीमारी में तड़के मिर्गी का अटैक आता था. वह बेहोश होकर गिर पड़ता था. बाद में उसकी मौत हो जाती थी. इस बीमारी को मस्तिष्क ज्वर से जोड़ कर देखा जाने लगा. लेकिन 2014 में नेशनल

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) और इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने संयुक्त रूप से संबंधित बीमारी का सघन अध्ययन किया. अध्ययन के बाद स्पष्ट हुआ कि ज्यादा प्रमाण में रात के समय भोजन न कर लीची का सेवन ज्यादा मात्रा में करने से यह बीमारी होती है. एनसीडीसी के संयुक्त निदेशक व अनुसंधान प्रमुख डॉ. आकाश श्रीवास्तव ने मुंबई में पिछले दिनों हुई 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल न्यूरोलॉजी कांफ्रेन्स' में यह जानकारी प्रस्तुत की.

डॉ.श्रीवास्तव ने बताया कि लीची में हायपोग्लोसिन ए और एमपीसीजी रसायन रहता है, जो रक्त में शुगर का प्रमाण कम करता है जबकि अन्य विषैले पदार्थ की मात्रा शरीर में बढ़ती है. ग्लूकोज तैयार होने की प्रक्रिया बाधित होती है.

लीची के बगीचे में बच्चे दिनभर खूब लीची खाते थे, रात में खाना नहीं खाते थे जिससे जहरीले रसायन खून में बनते थे.

विवाद मुक्त गांव अभियान से 9 जिलों ने फेरा मुंह

पहले नंबर पर रहने वाले बुलढाणा का भी समावेश

संवाददाता, 26 जुलाई

खामगांव- महात्मा गांधी विवाद मुक्त गांव अभियान कार्यक्रम में वर्ष 2015-16 में बुलढाणा समेत राज्य के 9 जिले शामिल नहीं हुए. विवाद मुक्ति में राज्य में पहले क्रमांक पर रहने वाले बुलढाणा जिले ने भी इस जन उपयोगी अभियान से मुंह फेर लेने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रह है. गांव के विवाद गांव में ही हल करने के लिए राज्य सरकार ने 2007 में महात्मा गांधी विवाद मुक्त गांव योजना शुरू की, लेकिन अब इस योजना की ओर अनदेखी की जा रही है, गत वर्ष राज्य के 9 जिले इसमें शामिल नहीं हुए. इसमें बुलढाणा जिले के साथ जालना, बीड़, नांदेड़, गड़चिरोली, सांगली, नांदुरबार, रायगड़ आदि जिलों का समावेश हैं.

सरकार ने जारी किए परिपत्र में बुलढाणा जिला स्वयं मूल्यांकन में शामिल नहीं हुआ ऐसा लिखा है. वर्ष 2015-16 में राज्य के 154 गांव विवादमुक्त हुए हैं. इसमें सबसे अधिक 34 गांव यवतमाल जिले के हैं. इन गांवों को जल्दी पुरस्कृत किया जाएगा. गांवों ने स्वयं मूल्यांकन के तहत गांव विवाद मुक्त घोषित किए गए. इन गांवों का 5 मई 2016 से लेकर 5

जून 2016 तक मूल्यांकन किया या. इसमें 154 गांव पुरस्कार के लिए पात्र ठहरे. 20 जून से 20 जुलाई तक इन गांवों का जिला बाह्य मूल्यांकन किया गया, लेकिन इसमें बुलढाणा जिले के एक भी गांव से पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं बुलवायी. साथ ही सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं दी.

राज्य में 2015-16 में इस अभियान को कम प्रतिसाद मिला. परिणाम स्वरूप विवाद मुक्त गांवों की संख्या 154 रही. बुलढाणा जिले में आरंभ के कुछ साल यह मुहिम गति से चलाई गई. गांवों में विवाद मुक्ति का वातावरण निर्माण होकर पुरस्कार प्राप्त करने की स्पर्धा होती थी. ग्रामस्थ और पुलिस अधिकारी इसमें उत्साह से शामिल होते थे, लेकिन कुछ वर्षों से यह उत्साह कम होता गया. कई गांवों में कागजात पर यह काम चलता रहा, लेकिन हाल ही में यह योजना सभी स्तर से पीछे रह गई है.

'इस अभियान को अब स्पर्धा के दृष्टि से नहीं तो जरूरत को समझकर अमल करना जरूरी हो गया है. महात्मा गांधी विवाद मुक्त गांव अभियान की ओर सरकारी स्तर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. बुलढाणा जिले के सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, पुलिस विभाग और नागरिकों के सहयोग से इस योजना के माध्यम से गांवों में शांति कायम रहने में बड़ी मदद हो सकती है.

जीएसटी अनुदान के लिए चुंगी को बनाएं आधार

मुख्यमंत्री के समक्ष केंद्रीय मंत्री ने रखा प्रस्ताव

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

नागपुर- जीएसटी से नागपुर मनपा को मिली मायूसी के बाद केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के नेतृत्व में मंगलवार को मुंबई में मनपा के अधिकारी व पदाधिकारियों ने फिर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से मुलाकात की. केंद्रीय मंत्री गड़करी ने बैठक में जीएसटी अनुदान के लिए एलबीटी की जगह चुंगी को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा. इस पर मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग और वित्त विभाग को चुंगी के आधार पर जीएसटी अनुदान का आंकलन करने के निर्देश दिए. उसके आधार पर जीएसटी अनुदान की राशि तय करने के निर्देश दिए. जीएसटी अनुदान को बढ़ाने और नाग नदी पुनर्जीवन प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की अध्यक्षता में मुंबई के विधान भवन में बैठक हुई. बैठक में केंद्रीय मंत्री गड़करी, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, महापौर नंदा जिचकार, पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, नगर विकास के प्रधान सचिव नितिन करीर, वित्त विभाग के प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, जलसंपदा विभाग के प्रधान सचिव आई.एस. चहल, पूर्व महापौर प्रवीण दटके, स्थायी समिति सभापति संदीप जाधव, मनपा आयुक्त अश्विन मुदकर, डॉ. म्हैसेकर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डॉ. रामनाथ सोनवणे, सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम आदि उपस्थित थे. नागपुर मनपा की तरफ से चुंगी को आधार बनाकर जीएसटी अनुदान का साल का 1065 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था. लेकिन एलबीटी को आधार बनाकर जीएसटी का आंकलन किया गया, जिससे नागपुर मनपा को जीएसटी एडवांस के तौर पर जुलाई महीने में 42.44 करोड़ रुपए अनुदान के तौर पर मिला. यह एलबीटी से भी कम अनुदान है. मनपा की स्थिति को देखते हुए गड़करी ने मुख्यमंत्री से चर्चा का निर्णय लिया.

डेढ़ घंटे तक चली बैठक में गड़करी ने कहा कि एलबीटी लागू होने से कई महानगरपालिकाओं को नुकसान हुआ है. इसी वजह से एलबीटी के पहले की व्यवस्था को जीएसटी के आंकलन के लिए आधार बनाया जाना चाहिए. सूत्रों के अनुसार केवल नागपुर मनपा के लिए बदलाव होना मुश्किल है. ऐसे में जिन महानगरपालिकाओं को एलबीटी लागू होने से नुकसान हुआ, उन्हें आज की बैठक में दिए गए आदेश से कुछ फायदा हो सकता है.

पायलट्स विमान के पहिए बंद करना भूले

एयर इंडिया फ्लाइट की कराई इमर्जेंसी लैंडिंग

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

नागपुर- सैकड़ों यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाले विमान के पायलट कई बार अपनी लापरवाही से उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं. ऐसे ही एक वाकये में एयर इंडिया के कोलकाता से मुंबई जाने वाले विमान के यात्री उस समय मुश्किल में आ गए जब पायलट्स विमान के पहिए बंद करना ही भूल गए. कोलकाता से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट के पायलट्स टेक ऑफ करने के बाद विमान का पहिया बंद करना भूल गए. उड़ान की आधी दूरी तय करने के बाद उन्हें अपनी इस गलती का एहसास तब हुआ, जब फ्लाइट का फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, मजबूरी में विमान को डायवर्ट करके नागपुर में उतारना पड़ा. घटना के बाद दोनों

पायलट्स को ड्यूटी से हटा दिया गया है.सूत्रों के अनुसार कोलकाता से सुबह 9.30 बजे उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई 676 के पायलट्स ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्लेन के पहिए बंद नहीं हैं, जबकि ऐसा करना जरूरी होता है. नियमानुसार टेक ऑफ के बाद पायलट्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि लैंडिंग गियर को बंद कर दिया जाए, लेकिन पायलट्स ने ऐसा नहीं किया. उनकी इस गलती की वजह से ईंधन की खपत तेजी से होने लगी और इमर्जेंसी में प्लेन को डायवर्ट करके यहां उतारना पड़ा. उड़ान के दौरान पायलट्स को बीच-बीच में फ्यूल भी चेक करना होता है, लेकिन इस फ्लाइट के पायलट्स ने ऐसा नहीं किया. टेक ऑफ करने से पहले प्लेन में उड़ान के लिए पर्याप्त फ्यूज मौजूद था.

अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी 'ग्रोथ इंजन'

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने बताया सकारात्मक आर्थिक सुधार

नागपुर- केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये 'ग्रोथ इंजिन' सिद्ध होगा. इससे जिस राज्य में उत्पादन होगा उस राज्य के राजस्व में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी. अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली प्रताड़ना बंद होगी. पारदर्शी कर वसूली होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा. डा. वसंतराव देशपांडे सभागृह में हितवाद की ओर से गोपालकृष्ण गोखले स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया था. इसमें 'जीएसटी और भारतीय अर्थव्यवस्था' विषय पर वे बोल रहे थे. इस अवसर पर महापौर नंदा जिचकार, हितवाद के प्रबंध संचालक राजेन्द्र पुरोहित, संपादक विजय फणशीकर, केन्द्रीय

जीएसटी के प्रमुख आयुक्त ए.के.पांडे, राज्य जीएसटी मुख्य आयुक्त पी.के.अग्रवाल प्रमुखता से उपस्थित थे.गड़करी ने आगे कहा कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान अत्यधिक है.अब तक दुनिया के 165 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है. देश में आर्थिक सुधार करने के लिये यह कर जरूरी है. भारत में वस्तु-माल का परिवहन खर्च (लॉजिस्टिक कॉस्ट) 18 प्रतिशत होगा.यह खर्च चीन में 8 से 10 प्रतिशत, यूरोप में 10 से 12 प्रतिशत है. इसके कारण निर्यात क्षेत्र में अन्य की तुलना में हम पिछड़ जाते हैं. जीएसटी के कारण 17 कर और 22 सेस (अधिभार) खत्म हो गए हैं. कर में सुलभता आई है. जीएसटी के कारण लायसेंस व इंस्पेक्टर राज को दूर कर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को गति मिली है. जीएसटी का सर्वाधिक फायदा नागपुर को मिलेगा. नागपुर के रिंग रोड पर लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा जिससे नागपुर एक लॉजिस्टिक केन्द्र के रूप में उभरेगा.

आज का इतिहास 27 जुलाई

1655 स्वीडन नरेश चार्ल्स दसवें ने पोलैंड पर हमला किया.

1795 स्पेन ने फ्रांस से शांति संधि की.

1839 चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम युद्ध शुरु हुआ.

1889 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी नाम से खुली.

1894 कोरिया ने चीन के खिलाफ जंग का ऐलान किया.

1933 इराक में सीरियाई ईसाईयों का संहार हुआ.

1965 उत्तर वियतनाम के प्रक्षेपास्त्र ठिकानों पर अमरीका ने हमला किया.

1972 नक्सली आंदोलन के जनक चारु मजूमदार का निधन जेल में हुआ.

1978 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की स्वतंत्रता के बारे में पश्चिमी देशों की योजना स्वीकार की.

2002 उप राष्ट्रपति कृष्णकांत का नई दिल्ली में निधन हुआ.

2002 निशानेबाज अभिनव बिन्द्रा तथा समीर आंबेकर ने 17 वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता.

2007 ब्रिटेन के ग्लासगो में आतंककारी हमले की साजिश के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार किए गए भारतीय डाक्टर हनीफ को जेल से रिया किया.

जयपुर के बाद अब नागपुर सिटी को बदलेगी मेट्रो

'म्हारी मेट्रो' के अध्ययन दौरे के दौरान कई रोचक जानकारियां हुई उजागर

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

नागपुर- राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में मेट्रो रेल (म्हारी मेट्रो) भले ही एक कॉरिडोर में चल रही है, लेकिन इसने वहां के लोगों की जिदंगी को बदलकर रख दिया है. अब बारी नागपुर की है. यहां दोनों कॉरिडोर में मेट्रो रेल (माझी मेट्रो)प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य साथ-साथ पूरा हो रहा है. इससे शहरवासियों के जीवन में मेट्रो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन लाएगी. यह भरोसा उस वक्त और भी मजबूत हो गया जब नागपुर की मीडिया म्हारी मेट्रो के अध्ययन दौरे के लिए जयपुर गई. इस दौरे के दौरान जयपुर और नागपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट के बीच कई समानताएं और अंतर नजर आए.नागपुर में दोनों कॉरिडोर का काम एक साथ : नागपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य दोनों यानी नॉर्थ-साउथ और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर में एक साथ चल रहा है. इससे राइडरशिप के मामले में जयपुर सहित अन्य मेट्रो की तुलना में नागपुर की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद है. जयपुर मेट्रो में फेज-1 ए के तहत 9.6 किमी में मेट्रो चल रही है. फेज-1 बी में 2.3 किमी के मार्ग और दो मेट्रो स्टेशनों का काम चल रहा है. फेज-2 में 24 किमी (10 किमी अंडरग्राउंड) के मेट्रो कॉरिडोर का डीपीआर बन गया है. यह काम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत साकार करने का निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है.

सोलर एनर्जी जनरेशन पर जोर

जयपुर के मानसरोवर मेट्रो डिपो में 100 किलावॉट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है. यहां के मेट्रो स्टेशनों की छतों पर भी सोलर पैनल लगाने का निर्णय जयपुर मेट्रो रेल कॉपोरेशन ने लिया है. जबकि, नागपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट के मिहान, हिंगना डिपो में सोलर एनर्जी जनरेट की जा रही है. मेट्रो स्टेशनों पर भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे.

फ्रांस की कंपनी करेगी डीपीआर में संशोधन

जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 24 किमी के सेंकड फेज के डीपीआर (विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट) में संशोधन का काम फ्रांस की कंपनी को दिए जाने की जानकारी जयपुर मेट्रो रेल कॉपोरेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अश्विनी सक्सेना ने दी. वे अध्ययन दौरे पर जयपुर आए नागपुर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के बी कैटेगरी के शहरों में जयपुर ऐसा शहर है, जहां सबसे पहले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम पूरा होकर ट्रेन चलने लगी है. इसके सेकेंड फेज के लिए विदेशी कंसल्टेंट से चर्चा कर डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है. फ्रांस की एक कंपनी को यह काम दिया गया है. सेकेंड फेज का काम शुरू होने पर यह काम 5 साल में पूरा हो जाएगा. दोनों चरण पूरे होने पर जयपुर मेट्रो 36 किमी की हो जाएगी. इस अवसर पर जयपुर मेट्रो रेल कॉपोरेशन के डायरेक्टर (कॉपोरेट अफेयर्स) राजेश अग्रवाल, डायरेक्टर (फाइनेंस) डॉ. बृजभूषण शर्मा, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अखिलेश कुमार शर्मा, मैनेजर(ऑपरेशन्स) शरदकुमार श्रीवास्तव, मैनेजर (रोलिंग स्टॉक) आर.एस. रेगर, जनसंपर्क अधिकारी शरद कुमार उपस्थित थे.

झूठे अपराध दर्ज करने वाले अधिकारी पर करें कार्रवाई

पुसद के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के निर्देश

एड. अनिल ठाकुर की जानकारी

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

यवतमाल- वरिष्ठ अधिकारी के दबाव में झूठे अपराध दर्ज कर हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश पुसद के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने दिए. अपराध दर्ज करने वाले तत्कालीन उपनिरीक्षक ने वैसा प्रतिज्ञा पत्र देने के बाद अदालत ने यह आदेश देने की जानकारी एड. अनिल ठाकुर ने पत्र-परिषद में दी.

पुसद के एड. अनिल ठाकुर के खिलाफ 13 मार्च 2009 को तत्कालीन पुसद शहर के थानेदार ज्ञानेश्वर घुगे ने निजी कारणों से समाज में विवाद निर्माण करने का अपराध दर्ज किया. साथ ही आचार संहिता लागू रहते हुए बिना अनुमति पत्रक निकालना आदि गंभीर अपराध दर्ज किए. साथ ही शांति समिति सदस्य के नाते एक विवाद हल करने के लिए गए ठाकुर के

साथ थानेदार ज्ञानेश्वर कडू ने मारपीट की.

उसके बाद अनिल ठाकुर के विरोध में 16 मार्च 2009 को सरकारी काम में रुकावट पैदा करने, कानून व्यवस्था खतरे में आने का प्रयास करने के अपराध दर्ज किए. इस पुलिस कार्रवाई के विरोध में एड. अनिल ठाकुर ने पुसद कार्रवाई के विरोध में एड. अनिल ठाकुर ने पुसद प्रथम श्रेणी न्यायालय में याचिका दायर की.

इस मामले में अपराध दर्ज करने वाले पुलिस उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम दशरथ इटनारे ने अदालत में प्रतिज्ञा पत्र पेश कर एड. अनिल ठाकुर के विरोध में थानेदार ज्ञानेश्वर घुगे के निर्देश से झूठा अपराध दर्ज करने की बात स्वीकार की.

बाद में अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनकर यह मामला गंभीर बताया. पुलिस अधिकारी ने निजी बदला लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. साथ ही इसके लिए अदालत का भी इस्तेमाल किया. पुलिस अधिकारी से हुई यह गलती किसी भी हाल में माफ करने जैसी नहीं है. इसमें एसपी को संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी अनंता बाजड़ ने दिया.

नगर परिषद कार्यालय मोर्शी, जिल्हा अमरावती
ई-निवीदा सूचना (तीसरी वेळ)
क्रमांक/नपामो/जाक्र/बांध/निवीदासुचना/कावि-1609/17 दिनांक 25.07.2017

सर्वसाधारण माहीती करीता प्रसिध्द करण्यात येते की, नगर परिषद मोर्शी ला नगर परिषद निधी मधुन खालील प्रमाणे बांधकाम करावयाचे आहे. तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे योग्य त्या वर्गातील पंजीबध्द कंत्राटदारांकडुन टक्केवारी दरात सिलबंद निवीदा खालील कामाकरीता मागविण्यात येत आहे. ई-निवीदा प्रसिध्दीचा तपशिल - Tender ID -2017 DMA 232809-1

ई-निविदा प्रसिध्दी	
ई-निविदा दाखल करण्याची सुरुवात दिनांक	26.07.2017 सकाळी 11.00 वाजेपासुन
ई-निविदा दाखल करण्याची अंतिम दिनांक	07.08.2017 सायंकाळी 5.45 वाजेपर्यंत
ई-निविदा उघडण्याचा दिनांक (Technical)	09.07.2017 सकाळी 11.00 वाजता शक्य झाल्यास

(Financial) ई-निविदा उघडण्याची दिनांक व वेळ Mail व SMS द्वारे कळविण्यात येईल.

सदर निवीदा ह्या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर पहावयास मिळेल निवीदा या ऑनलाईन पध्दतीने भरणा करावयाच्या आहेत. सदर निवीदेतील अनामत रक्कमेच्या व निवीदा प्रपत्राचा भरणा ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येईल. सर्व अटी व शर्ती निवीदा सुचने प्रमाणे पहावयास मिळेल.

सौ.शिला अ. रोडे अध्यक्ष | जितेंद्र प्र. गेडाम उपाध्यक्ष | मनोहर न. शेंडे बांधकाम सभापती | पी.डी. राठोड मुख्याधिकारी

नगर परिषद कार्यालय मोर्शी, जिल्हा अमरावती